

अरुमुघम (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य

बनाम

सुंदरम्बल एवं एक अन्य

अप्रैल 29, 1999

[एम. जगन्नाथ राव और एन. संतोष हेगड़े, न्यायमूर्तिगण]

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908: द्वितीय अपील

द्वितीय अपील-द्वितीय अपीलीय न्यायालय-तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की शक्ति-
अपीलकर्ता-वादी द्वारा वाद संपत्ति के स्वत्व की घोषणा और स्थायी व्यादेश के लिए दायर वाद-
विचारण न्यायालय द्वारा वाद खारिज-निष्कर्ष कि वादी ने अपने पिता की संपत्ति पर स्वत्व
साबित नहीं किया था और वह कब्जे में भी नहीं था-प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वाद को
स्वीकार किया और विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया-द्वितीय अपील में उच्च
न्यायालय ने तथ्यों के निष्कर्षों को उलट दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल
किया-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता-प्रतिवादी द्वारा अपील-निर्णीत-द्वितीय अपीलीय
न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि
प्रथम अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के तर्क से पूरी तरह अवगत नहीं हुआ था-प्रथम
अपीलीय न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करे और
एक पक्ष के साक्ष्य को स्वीकार करने या दूसरे पक्ष के साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए अपने
स्वयं के कारण दे-द्वितीय अपीलीय न्यायालय के लिए यह केवल इस आधार पर अनुमेय नहीं है
कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से अवगत नहीं
हुआ था-उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया गया।

एस.वी.आर. मुदलियार बनाम रजबु एफ. बुहारी, [1995] 4 एससीसी 15, विधि की उपेक्षा में दिया गया निर्णय।

रानी हेमंता कुमारी देबी बनाम महाराजा जगदीन्द्र नाथ रॉय बहादुर, 16 एमएलजे 272(पीसी), अप्रयोज्य निर्णीत।

वी. रामचन्द्र अय्यर एवं एक अन्य बनाम रामलिंगम चेट्टियार एवं एक अन्य, एआईआर (1963) एससी 302, पर अवलंबन।

मंगम्मा बनाम पैडय्या, एआईआर (1941) एमएडी 393, संदर्भित।

प्रमाण का भार-अभिनिर्धारित कि प्रासंगिक नहीं है जब दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हों-यह केवल तभी प्रासंगिक होगा यदि कोई व्यक्ति जिस पर प्रमाण का भार था, वह पूरी तरह से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1999 की दीवानी अपील संख्या 2709।

1983 की एस.ए. संख्या 1946 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 30.9.97 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं के लिए वी. प्रभाकर और सुश्री रेवती राघवन।

उत्तरदाताओं के लिए एस. बालकृष्णन और एस.आर. हेगड़े।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया:

विशेष अनुमति प्रदान की गई।

यह 30 सितंबर, 1997 के द्वितीय अपील संख्या 1946 वर्ष 1983 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मृत वादी के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा दायर एक अपील है। उक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने 30.6.83 के अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को उलट

दिया और 1979 की ओ.एस. संख्या 187 में 12.5.82 के विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल किया।

वादी ने वाद संपत्ति के स्वत्व की घोषणा और स्थायी व्यादेश के लिए एक वाद दायर किया, जिसमें उसने स्वर्गीय हरितीर्थम और मारियायी का पुत्र होने का दावा किया। उसके अनुसार उसके पिता उक्त हरितीर्थम की मृत्यु 40 वर्ष पहले और उसकी माता मारियायी की मृत्यु वाद से 5 वर्ष पहले हुई थी। यह कहा गया था कि वादी 25 वर्षों से अधिक समय से लकवा से पीड़ित था। यह भी कहा गया था कि कई वर्ष पहले प्रथम प्रतिवादी और उसकी माता वाद वाले गाँव में निवास कर रहे थे और द्वितीय प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी का पति था। प्रथम प्रतिवादी स्वर्गीय हरितीर्थम और मारियायी की पुत्री नहीं थी। प्रथम प्रतिवादी की माता की मृत्यु वाद से 4 या 5 वर्ष पहले हुई थी और उसके बाद प्रथम प्रतिवादी ने अपने नाम पर पट्टा बदलवा लिया और वादी के अधिकार और हित से इनकार किया। वादी ने कहा कि प्रतिवादी वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे थे और इसलिए उसने स्वत्व की घोषणा और स्थायी व्यादेश का दावा किया।

प्रतिवादियों ने मारियायी के स्वत्व से इनकार किया। उन्होंने तर्क दिया कि वादी एक ढोंगी था और वह स्वर्गीय हरितीर्थम और स्वर्गीय मारियायी का पुत्र नहीं था। उन्होंने कब्जे में होने का दावा भी किया।

वादी ने अपने मामले के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी के मामले के समर्थन में चार साक्षियों अ.सा.-1 से अ.सा.-4 का परीक्षण किया गया और वादी ने सोलह दस्तावेज दाखिल किए। प्रतिवादियों ने अपने मामले के समर्थन में 7 साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया और सात दस्तावेज दाखिल किए। संबंधित पक्षों द्वारा रखे गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादी ने यह

स्थापित नहीं किया था कि वह स्वर्गीय हरितीर्थम और मारियायी का पुत्र था। इसलिए विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि वादी ने अपने पिता की संपत्ति पर अपना स्वत्व साबित नहीं किया था और साक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ कि वादी कब्जे में नहीं था और इसलिए वादी स्वत्व की घोषणा और न ही स्थायी व्यादेश का हकदार था। विचारण न्यायालय ने निर्णीत किया कि प्रथम प्रतिवादी हरितीर्थम और मारियायी की एकमात्र पुत्री थी। वाद खारिज कर दिया गया था।

उक्त निर्णय के विरुद्ध, वादी ने विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, पुदुकोट्टई के समक्ष अपील संख्या 138/82 प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर चर्चा की और उसे स्वीकार किया। इसने वादी द्वारा उसमें यह प्रविष्टि साबित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत मतदाता सूची पर भी अवलंबन किया कि वह हरितीर्थम का पुत्र था। मतदाता सूची को अन्य दस्तावेजों के साथ स्वीकार कर लिया गया। अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया। इसने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर भी विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रतिवादी द्वारा स्थापित मामला स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसने यह निष्कर्ष भी दिया कि उचित जाँच के बिना और प्रथम वादी की कमजोरी और बीमारी का लाभ उठाकर पट्टा प्रथम प्रतिवादी के नाम पर बदल दिया गया था। प्रतिवादी ने राजस्व विभाग में हेरफेर किया था और पट्टा हस्तांतरित करवा लिया था। परिणामस्वरूप अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और निर्णीत किया कि वादी हरितीर्थम और मारियायी का पुत्र था और अपने पिता की संपत्ति का हकदार था। अपीलीय न्यायालय ने संपत्ति के कब्जे के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को भी उलट दिया और निर्णीत किया कि वादी वाद की दिनांक पर कब्जे में था। परिणामस्वरूप, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वत्व की घोषणा और स्थायी व्यादेश प्रदान किए गए।

द्वितीय अपील में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रारंभ में विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु तैयार किया:

"क्या मतदाता सूची में प्रविष्टियों को वंशावली और कठिनाई स्थापित करने के उद्देश्यों के लिए निर्णायक साक्ष्य माना जा सकता है और, यदि हाँ, तो इसका प्रमाणिक मूल्य क्या है?"

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मतदाता सूची स्वीकार्य नहीं थी। फिर वे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़े। विद्वान न्यायाधीश का विचार था कि अपीलीय न्यायालय ने वादी के बजाय प्रथम प्रतिवादी पर प्रमाण का भार डाला था। विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्य पर ऐसे चर्चा की जैसे कि वह प्रथम अपील पर विचार कर रहे हों और तथ्यों के निष्कर्षों को उलट दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय को तथ्य के प्रश्नों पर निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। अपीलीय न्यायालय गुण दोष के आधार पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार नहीं कर सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि प्रथम प्रतिवादी ने एक विशिष्ट मामला रखा था कि वादी एक ढोंगी था और इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से प्रथम प्रतिवादी पर प्रमाण का भार डाला था। अपीलीय न्यायालय सही रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादी संपत्ति के कब्जे में था। यह मानते हुए भी कि मतदाता सूची स्वीकार्य नहीं थी, वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर्याप्त था और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को बहाल किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर ध्यान नहीं दिया था और उक्त कारणों से अवगत नहीं हुआ था। अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिए इस न्यायालय के [1995] 4 एससीसी 15 एस.वी.आर. मुदलियार बनाम रजबु एफ. बुहारी के निर्णय पर अवलंबन किया कि यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए सभी कारणों पर ध्यान नहीं दिया है और उनके साथ पूरी तरह अवगत नहीं हुआ है, तो द्वितीय अपीलीय न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। उपरोक्त निर्णय से निम्नलिखित गद्यांश पर अवलंबन किया गया था:

"इसलिए, हम उत्तरदाता के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर इस तथ्य को तय करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं; बल्कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ऐसा करेंगे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस साक्ष्य को विचारण न्यायाधीश के हाथ में बेहतर व्यवहार मिला है, जिन्होंने यह मानते हुए कि कमल ने प्रतिवादियों के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य किया था, कई परिस्थितियों का भी उल्लेख किया। श्री परासरन ने ट्रक दिया कि यद्यपि अपीलीय न्यायालय को तथ्य के प्रश्न पर भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा विचारण न्यायाधीश द्वारा प्रश्नगत निष्कर्ष पर पहुंचने में दिए गए कारणों पर ध्यान देने के बाद किया जाना चाहिए। वास्तव में, श्री परासरन के अनुसार एक अपीलीय न्यायालय को अपील के अधीन निर्णय में हस्तक्षेप इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सही नहीं है, बल्कि तब करना चाहिए जब उसे गलत दिखाया गया हो, जैसा कि डॉलर कंपनी बनाम कलेक्टर ऑफ मद्रास, 1975 (2) एससीसी 730 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी के संबंध में, श्री वैद्यनाथन का तर्क यह है कि उसमें जो कहा गया था वह

तब लागू होने के लिए था जब यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत किसी मामले की जाँच करता है। हालाँकि, हमें नहीं लगता कि जो देखा गया उसका यह अर्थ निकाला जा सकता है।

विधिक सिद्धांत को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि तथ्य के निष्कर्ष को उलटने से पहले, *अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को ध्यान में रखना होता है।* हमारा यह विचार प्रिवी काउंसिल द्वारा *रानी हेमंता कुमारी देबी बनाम महाराजा जगदीन्द्र नाथ राँय बहादुर*, 10 सीडब्ल्यूएन 630 (पीसी) सी= 16 एमएलजे 272 में कही गई बातों से समर्थन पाता है, जिसमें फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के अपीलीय निर्णय को "सतर्क और सक्षम" मानते हुए यह कहा गया था कि यह उस निर्णय से पूरी तरह अवगत नहीं हुआ जिसकी यह समीक्षा करता है, और वास्तव में अधीनस्थ न्यायाधीश के तर्कों पर कभी चर्चा या उल्लेख भी नहीं करता है।"

उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तदनुसार तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए सभी कारणों पर विचार नहीं किया था और इसलिए उक्त न्यायालय के लिए विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटना अनुमेय नहीं था और ऐसे संदर्भ में, उच्च न्यायालय के लिए अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अपास्त करना अनुमेय होगा। अधिवक्ता ने बताया कि उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने *रानी हेमंता कुमारी देबी बनाम महाराजा जगदीन्द्र नाथ राँय बहादुर*, 16 एमएलजे 272 (पीसी) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर अवलंबन किया था, जहाँ ऐसा प्रस्ताव रखा गया था।

विचार के लिए बिंदु यह है कि क्या उच्च न्यायालय इस आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पहुँचे गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में सही था कि अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों पर ध्यान नहीं दिया है?

इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष *वी. रामचन्द्र अय्यर और एक अन्य बनाम रामलिंगम चेट्टियार और एक अन्य*, एआईआर (1963) एससी 302 में इसी तरह का प्रश्न उठा था। *मंगम्मा बनाम पैडय्या*, एआईआर (1941) एमएडी 393 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंबन करते हुए, उस मामले में उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसी तरह का तर्क उठाया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर उलट नहीं सकता कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए सभी कारणों पर ध्यान नहीं दिया था या वह विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से अवगत नहीं हुआ था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"श्री चटर्जी ने तब *मंगम्मा बनाम पैडय्या*, 53 मैड एल डब्ल्यू 160: एआईआर (1941) मैड 393 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर दृढ़ अवलंबन किया है। उस मामले में न्यायमूर्ति पाण्डरंग राव ने अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ प्रथम अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटने वाले अपने निर्णय में मामले में साक्ष्य के साथ पूरी तरह अवगत होने में या अपने निष्कर्षों के समर्थन में विचारण न्यायालय के तर्कों का सामना करने में विफल रहता है, अपीलीय न्यायालय के निर्णय को प्रक्रिया में एक त्रुटि द्वारा दूषित माना जाना चाहिए और इसलिए द्वितीय अपील में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये टिप्पणियाँ निस्संदेह यह तर्क देने में श्री चटर्जी का समर्थन करती हैं कि इस मामले में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को उलटने में उच्च न्यायालय न्यायोचित था। हमारी राय में, हालांकि, निर्णय में की गई व्यापक टिप्पणियाँ धारा 100 के तहत द्वितीय अपीलों से निपटने में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमाओं के बारे में सही विधिक स्थिति का सही ढंग से

प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। यह निर्णय दर्शाता है कि विद्वान न्यायाधीश ने सोचा कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायाधीश की राय के विरुद्ध नहीं जाने के लिए बाध्य था, जिसके पास मौखिक साक्ष्य की विश्वसनीयता पर निर्णय लेने में अपने समक्ष साक्षियों को देखने का अवसर था; और उन्होंने कहा है कि जब तक अच्छे कारण न दिए जाएँ, इस तरह के मामलों पर विचारण न्यायाधीश के निष्कर्ष के साथ कोई भी हस्तक्षेप विधि में त्रुटिपूर्ण माना जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि विधि का यह कथन धारा 100 के प्रावधानों के साथ असंगत है।

रानी हेमंता कुमारी देबी बनाम महाराजा जगदीन्द्र नाथ राँय बहादुर, 16 मैड एलजे 272 (पीसी) में, प्रिवी काउंसिल ने निस्संदेह यह टिप्पणी की है कि यह बेहतर है कि अपीलीय न्यायालय जब भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उलटता है, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह अवगत हो और उसमें दिए गए तर्कों का सामना करे। ये टिप्पणियाँ, हालांकि, धारा 100 के प्रावधानों के दायरे को निर्धारित करने में हमारी सहायता नहीं करती हैं। वे एक अपील में की गई थीं जो उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ प्रिवी काउंसिल के समक्ष गई थी जब अपीलीय पीठ प्रथम दृष्ट्या न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ दायर *प्रथम अपील* पर विचार कर रही थी। उच्च न्यायालय ने प्रथम न्यायालय के निर्णय को उलट दिया था; और उक्त उलटने वाले निर्णय के औचित्य या शुद्धता पर विचार करते हुए, प्रिवी काउंसिल ने टिप्पणी की कि अपीलीय निर्णय उस निर्णय से पूरी तरह अवगत नहीं हुआ जिसे उसने उलट दिया था। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि उचित अपीलीय निर्णय की आवश्यकताओं के बारे में प्रिवी काउंसिल ने जो कहा है वह यह तर्क देने में श्री चटर्जी की सहायता नहीं कर सकता कि यदि तथ्य के प्रश्नों से निपटने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित निर्णय नहीं लिखा गया है,

तो तथ्य के इसके निष्कर्षों को धारा 100 के तहत चुनौती दी जा सकती है। उस प्रश्न पर अकेले धारा 100 के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए।

रामचन्द्र अय्यर के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के पूर्वोक्त निर्णय से, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने निर्णीत किया कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि प्रथम अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के तर्क से पूरी तरह अवगत नहीं हुआ था। प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करे और एक पक्ष के साक्ष्य को स्वीकार करने या दूसरे पक्ष के साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए अपने स्वयं के कारण दे। द्वितीय अपीलीय न्यायालय के लिए यह केवल इस आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना अनुमेय नहीं है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से अवगत नहीं हुआ था। *रामचन्द्र अय्यर* के मामले में इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय ने विशेष रूप से प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए *रानी हेमंता कुमारी देबी बनाम महाराजा जगदीन्द्र नाथ रॉय बहादुर*, 16 एमएलजे 272 (पीसी) को इस आधार पर अलग किया कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय प्रथम अपील पर विचार कर रहा था। उस संदर्भ में प्रिवी काउंसिल द्वारा की गई टिप्पणियाँ उन मामलों पर लागू नहीं होंगी जहाँ द्वितीय अपीलीय न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के उस निर्णय की शुद्धता पर विचार कर रहा था जिसने विचारण न्यायालय को उलट दिया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि *एस.वी.आर. मुदलियार (मृत)* द्वारा विधिक प्रतिनिधि और *अन्य बनाम रजबु बुहारी (मृत)* द्वारा विधिक प्रतिनिधि और *अन्य* के मामले में, न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने *वी. रामचन्द्र अय्यर* के मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर ध्यान दिए बिना एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया जहाँ इस

न्यायालय ने विशेष रूप से *रानी हेमंता कुमारी देवी* के मामले का उल्लेख किया था और इसे अलग किया था। इसलिए दो न्यायाधीशों की पीठ *रानी हेमंता कुमारी देवी* के प्रिवी काउंसिल मामले पर अवलंबन नहीं कर सकती थी। इसलिए, हम *एस.वी.आर. मुदलियार* के मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के बजाय *वी. रामचन्द्र अय्यर* के मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के दृष्टिकोण का पालन करना पसंद करते हैं।

प्रमाण का भार के प्रश्न पर हमारा विचार है कि यह मानते हुए भी कि दी.प्र.सं. की धारा 100 के संशोधित प्रावधान के संदर्भ में प्रमाण का भार प्रासंगिक है, वह तब प्रासंगिक नहीं होगा जब दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हों। यह केवल तभी प्रासंगिक होगा यदि कोई व्यक्ति जिस पर प्रमाण का भार था, वह पूरी तरह से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। वर्तमान मामले में दोनों पक्षों ने मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे और इसलिए यह मानते हुए भी कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के लिए यह कहना त्रुटिपूर्ण था कि यह साबित करने का प्रमाण का भार प्रथम प्रतिवादी पर था कि वादी हरितीर्थम का पुत्र नहीं था, हमारी राय में, इसका अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पहुँचे गए निष्कर्ष पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया था और वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार करना पसंद किया और इसने प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को भी अस्वीकार कर दिया। वास्तव में, उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने पर, हम इस धारणा के साथ रह जाते हैं कि उच्च न्यायालय ने सोचा कि यह मामले से ऐसे निपट रहा था जैसे कि यह एक प्रथम अपील हो। इसलिए, ऊपर दिए गए कारणों से, उच्च न्यायालय का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय बहाल किया जाता है।

अपील तदनुसार स्वीकृत की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

टी.एन.ए.

अपील स्वीकृत।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।